

## विचार बिन्दु

काम से शोक उत्पन्न होता है। -धम्पद

# क्या जातिगत आरक्षण वोट पाने की कुनीति है?

रा

एक मैथिली शरण गुप्त की एक कविता में भारतीय संस्कृति की महानता का जो परिचय कराया गया वह अभूतपूर्व है। हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के हेतु जो प्रावधान प्रियमल चेपर तीन व चेपर चार में किये हैं, वे देश की उच्च प्रम्परा और संस्कृति के अनुरूप हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में समता व समानता तथा अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विवेद का अधिष्ठित किया है, वह संविधान की विशेषता को इग्निट करता है और हमारी सदियों की उच्च संस्कृति को प्राप्तिकरता है। समता, समानता, समसरता और बहुस्वत्व की गतिशीलता ने निखारती है। समता, समानता, समसरता और प्रकार है:-

भारत माता का मरिंदर पर, समता का संबंध वहाँ

सबका, शिव कल्याण वहाँ है, पावे सभी प्रसाद वहाँ।

जाति, धर्म या सम्पदवाद का नहीं है भेदभाव वहाँ,

सबका स्वाधार, सबका आदर, सबका सम समान वहाँ।

सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिये आरक्षण के प्रावधान हैं संविधान के अनुच्छेद 16 में संविधान 103वें संसेधन अधिनियम, 2019 में अधिक रूप से दुर्बल बागों के लिये 10 प्रतिशत तक आरक्षण की बात आहत है। इसे पांच जैसा ऊपर लिया है आरक्षण का प्रारम्भ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ों की बात आहत है। और हमारी सदियों की उच्च संस्कृति करता है। समता, समानता, समसरता और बहुस्वत्व की गतिशीलता ने निखारती है। समता, समानता, समसरता और प्रकार का एक पेरा इस प्रकार है:-

केंद्र व राज्य सकारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिये सीटें आरक्षित करती हैं यह आरक्षण जाति के आधार पर है, जो जन्म से तय होती है।

देश में आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है:-

अनुसूचित जाति (SC) 15% आरक्षण

अनुसूचित जनजाति (ST) 7.5% आरक्षण

अन्य पिछड़ी वर्ग (OBC) 27% आरक्षण

कुल आरक्षण 49.5% आरक्षण (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय सीमा 50%)

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

सामाजिक वर्ग के सभी धर्मों के लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार

धर्म के लिये अनुसूचित जातियों की वात आहत है।

आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का उद्देश्य संसेधन विधेयक 2023 द्वारा आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ावा दिया गया है। 10 प्रतिशत EWS के के रूप में अन्य अधिनियम से कवर है।

बिहार के आरक्षण विधेयक के बाद, महाराष्ट्र में मराठाओं के लिये अलग से आरक्षण की मांग उठी है। शिक्षा व साकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया था। बायंड हाईकोर्ट ने उसे संघेतानिक माना। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह आरक्षण सुप्रीम धर्म तथा धर्मी पूर्ण में की गई सीमा का उल्लंघन है। विवाद चल रहे हैं। और कई राजनीतिक दलों ने जातितात जनगणना और आरक्षण को लेकर चुनावों में माहौल गर्म किया। जातिगत आरक्षण को जातिनीतिक हृष्यायर के रूप में काम में लेने का यह तरीका काम में लिया गया। कई राज्यों में 50 प्रतिशत सीमा, जिसे सुप्रीम कोर्ट के तर्क दिया गया था, उसे तो देखते हैं और कुछ सीमा को बढ़ावा दाते हैं।

आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का उद्देश्य संसेधन विधेयक 2023 द्वारा आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ावा 75 प्रतिशत करने का है। 10 प्रतिशत EWS के के रूप में अन्य अधिनियम से कवर है।

बिहार के आरक्षण विधेयक के बाद, महाराष्ट्र में मराठाओं के लिये अलग से आरक्षण की मांग उठी है। शिक्षा व साकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया था। बायंड हाईकोर्ट ने उसे संघेतानिक माना। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह आरक्षण सुप्रीम धर्म तथा धर्मी पूर्ण में की गई सीमा का उल्लंघन है। विवाद चल रहे हैं। और कई राजनीतिक दलों ने जातितात जनगणना और आरक्षण को लेकर चुनावों में माहौल गर्म किया। जातिगत आरक्षण को जातिनीतिक हृष्यायर के रूप में काम में लिया गया। कई राज्यों में 50 प्रतिशत सीमा, जिसे सुप्रीम कोर्ट के तर्क दिया गया था, उसे तो देखते हैं और कुछ सीमा को बढ़ावा दाते हैं।

आरक्षण विधेयक के लिये अलग से आरक्षण की मांग उठी है। और कुछ सीमा को बढ़ावा दाते हैं।

यह सही है कि दलियों का उत्तीर्ण हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछड़े प्रेसन को समाप्त करने के हेतु एक साहसरात्र कदम है। वे भी समता समानता के लिये अकेले हैं।

बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के बाद एक रूप से आरक्षण की मांग उठी है। शिक्षा व साकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया था। बायंड हाईकोर्ट ने उसे संघेतानिक माना। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह आरक्षण सुप्रीम धर्म तथा धर्मी पूर्ण में की गई सीमा का उल्लंघन है। विवाद चल रहे हैं। और कई राजनीतिक दलों ने जातितात जनगणना और आरक्षण को लेकर चुनावों में माहौल गर्म किया। जातिगत आरक्षण को जातिनीतिक हृष्यायर के रूप में काम में लिया गया। कई राज्यों में 50 प्रतिशत सीमा, जिसे सुप्रीम कोर्ट के तर्क दिया गया था, उसे तो देखते हैं और कुछ सीमा को बढ़ावा दाते हैं।

आरक्षण विधेयक के लिये अलग से आरक्षण की मांग उठी है। और कुछ सीमा को बढ़ावा दाते हैं।

बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के बाद एक रूप से आरक्षण की मांग उठी है। यह सही है कि दलियों का उत्तीर्ण हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछड़े प्रेसन को समाप्त करने के हेतु एक साहसरात्र कदम है। वे भी समता समानता के लिये अकेले हैं।

एक राष्ट्र है, किन्तु यह सही नहीं है, क्योंकि हमारा जननाना को आधार पर, समता के बाद एक राष्ट्र है। अतः हमें स्वीकार करना होगा जिसने जातितात जनगणना की मांग उठा रखे हैं तो पीछे एक राज्यों की गई सीमा का उल्लंघन है। एक और राज्य गांधी भी अब जनगणना को लेकर चुनावों में माहौल गर्म किया। जातिगत आरक्षण को जातिनीतिक हृष्यायर के रूप में काम में लिया गया। कई राज्यों में 50 प्रतिशत सीमा, जिसे सुप्रीम कोर्ट के तर्क दिया गया था, उसे तो देखते हैं और कुछ सीमा को बढ़ावा दाते हैं।

यह सही है कि दलियों का उत्तीर्ण हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछड़े प्रेसन को समाप्त करने के हेतु एक साहसरात्र कदम है। वे भी समता समानता के लिये अकेले हैं।

जातिगत आरक्षण अथवा जातिगत संविधान के बाद एक रूप से आरक्षण की मांग उठी है। यह सही है कि दलियों का उत्तीर्ण हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछड़े प्रेसन को समाप्त करने के हेतु एक साहसरात्र कदम है। वे भी समता समानता के लिये अकेले हैं।

जातिगत आरक्षण अथवा जातिगत संविधान के बाद एक रूप से आरक्षण की मांग उठी है। यह सही है कि दलियों का उत्तीर्ण हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछड़े प्रेसन को समाप्त करने के हेतु एक साहसरात्र कदम है। वे भी समता समानता के लिये अकेले हैं।

जातिगत आरक्षण अथवा जातिगत संविधान के बाद एक रूप से आरक्षण की मांग उठी है। यह सही है कि दलियों का उत्तीर्ण हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछड़े प्रेसन को समाप्त करने के हेतु एक साहसरात्र कदम है। वे भी समता समानता के लिये अकेले हैं।

जातिगत आरक्षण अथवा जातिगत संविधान के बाद एक रूप से आरक्षण की मांग उठी है। यह सही है कि दलियों का उत्तीर्ण हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछड़े प्रेसन को समाप्त करने के हेतु एक साहसरात्र कदम है। वे भी समता समानता के लिये अकेले हैं।

जातिगत आरक्षण अथवा जातिगत संविधान के बाद एक रूप से आरक्षण की मांग उठी है। यह सही है कि दलियों का उत्तीर्ण हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछड़े प्रेसन को समाप्त करने के हेतु एक साहसरात्र कदम है। वे भी समता समानता के लिये अकेले हैं।

जातिगत आरक्षण अथवा जातिगत संविधान के बाद एक रूप से आरक्षण की मांग उठी है। यह सही है कि दलियों का उत्तीर्ण हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछड़े प्रेसन को समाप्त करने के हेतु एक साहसरात्र कदम है। वे भी समता समानता के लिये अकेले हैं।

जातिगत आरक्षण अथवा जातिगत संविधान के बाद एक रूप से आरक्षण की मांग उठी है। यह सही है कि दलियों का उत्तीर्ण हुआ था और वे सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं और आरक्षण उनके पिछड़े प्रेसन को समाप्त